संख्या:-1190/78-1-2021-15आईटी/2020टीसी-1

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीएलसी।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 30 जुलाई 2021

विषयः उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत डिस्रप्टिव (Disruptive) टेक्नोलॉजी क्षेत्र के स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महाप्रबन्धक (नी0/प्र0) यूपीएलसी के पत्र संख्या-यूपीएलसीः स्टार्टअप:2021-22, दिनांक 28-07-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के उभरते हुए डिस्रप्टिव (Disruptive) टेक्नोलॉजी क्षेत्र यथा ई-कॉमर्स, ऑन लाईन न्यून आईटम, राईड-शेयरिंग ऐप, GPS Systems, Fintech, AI/ML/Cyber Security, Blockchain Big Data, Transport/Urban Mobility/E-Vehicle, Biotech, Health Care/E-Pharmacy Civil Aviation/Drones/Tourisim/Travel tech, labour laws, Pollution Control इत्यादि क्षेत्रों में कार्यरत स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु एक विस्तृत रुपरेखा बनाते हुए नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

30/07/2021

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव

Proposed rules and guidelines to enhance support to startups in disruptive sectors in Uttar Pradesh

All the sectors may be provided with sector specific funds for promoting Startups from disruptive sectors. In addition to above few of the rules which may be introduced sector wise are as given below:

(1) Transport/Urban mobility/ E-vehicle

(i) UP govt. may invite bootcamps/ startups to design AI based smart traffic solutions for cities

(2) Civil aviation/drones

(i) UP Govt. may provide licensing support to the startups working in creating drone based services

(ii) Govt. approved training site: Government land/ parks may be allowed in major cities like Lucknow, Ghaziabad, Greater Noida to enhance drone training & technology enhancement in UP.

(3) AI/ML/Cyber security

(i) Financial Grant for startups developing AI based health application

(4) Biotech/Healthcare/E-Pharmacy

(i) UP Govt. to constitute a panel of authorized hospitals which can be approached by a healthcare startup, registered in UP, for conducting clinical validation studies and clinical trials for their prototype or product testing. A mechanism to compensate these empanelled hospitals may be developed.

(5) AgriTech

(i) UP Govt. may invite Startups from Blockchain field to implement a solution on Seed/ Breed traceability in agriculture/ dairy sectors.

699
22.6.21

बैठक दिनांक 26-06-2021 पूर्वान्ह 12:00 बजे

संख्या-924/78-2-2021-135आईटी/2016

प्रेषक,

बराती लाल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, अशोकमार्ग लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, गोमतीनगर लखनऊ।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 22 जून, 2021

विषय:- साफ्टवेयर विकास एवं स्टार्ट-अप हेतु संस्थाओं को सूचीबद्ध किये जाने विषयक पूर्व में निर्गत गाइड लाइन्स में कतिपय संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-189/78-2-2021-135आईटी/2016 दिनांक 22-01-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- प्रकरण पर विचार विमर्श किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में **दिनांक 26-06-2021 मध्यान्ह 12:00 बजे सी ब्लाक, लोक भवन प्रथम तल स्थित सभा कक्षा-109 में बैठक आहूत की गयी है।**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त बैठक में निर्धारित तिथि व समय पर सुसंगत सूचनाओं सहित भिज्ञ अधिकारियों के साथ **स्वयं** प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इले0 विभाग, उ0प्र0शासन।
2- विशेष सचिव, (आर0 / के0वी0) आईटी एवं इले0 विभाग, उ0प्र0शासन।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव

6 July 12 noon

7.3.19
12-3-19

881
12-3-19

संख्या–127/78-2-2019-135आई.टी./2016

प्रेषक,

एम0बी0सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को, गोमती नगर, लखनऊ।
प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एल0सी0,10 अशोक मार्ग, लखनऊ।
प्रबन्ध निदेशक, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0/श्रीट्रान इंण्डिया लि0,।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 11 मार्च,2019

विषय: साफ्टवेयर विकास, मैनपावर आपूर्ति एवं स्टार्ट अप हेतु संस्थाओं को सूचीबद्ध किये जाने विषयक गाईड लाइन्स के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक,यूपीएलसी एवं अन्य के हस्ताक्षरित पत्र संख्या-यूपीएलसी/साफ्टवेयर/मैनपावर/स्टार्टअप/2018-19,दिनांक 18फरवरी2019,का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि साफ्टवेयर विकास, मैनपावर आपूर्ति एवं स्टार्ट अप हेतु संस्थाओं को सूचीबद्ध किये जाने विषयक संयुक्त हस्ताक्षरित गाईड लाइन्स पर शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। कृपया तदनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय,

(एम0बी0सिंह)
विशेष सचिव

उप महाप्रबन्धक / Sr Manager (Software)

12.03.2019

(कुमार प्रशान्त)
आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

22

संख्या–127/78-2-2019-135आई.टी./2016

प्रेषक,

एम0बी0सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को, गोमती नगर, लखनऊ।
प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एल0सी0,10 अशोक मार्ग, लखनऊ।
प्रबन्ध निदेशक, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0/श्रीट्रान इंण्डिया लि0,।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 11 मार्च,2019

विषय: साफ्टवेयर विकास, मैनपावर आपूर्ति एवं स्टार्ट अप हेतु संस्थाओं को सूचीबद्ध किये जाने विषयक गाईड लाइन्स के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक,यूपीएलसी एवं अन्य के हस्ताक्षरित पत्र संख्या-यूपीएलसी/साफफ्टवेयर/मैनपावर/स्टार्टअप/2018-19,दिनांक 18फरवरी2019,का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि साफ्टवेयर विकास, मैनपावर आपूर्ति एवं स्टार्ट अप हेतु संस्थाओं को सूचीबद्ध किये जाने विषयक संयुक्त हस्ताक्षरित गाईड लाइन्स पर शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। कृपया तदनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय,

(एम0बी0सिंह)
विशेष सचिव

सन्दर्भः यूपीएलसीःसाफ्टवेयरःमैनपावरःस्टार्टअप/2018-19

दिनाँकः 18 फरवरी, 2019

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव
आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

महोदय,

दिनाँक 13 फरवरी, 2019 को आहूत समीक्षा बैठक में आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन के नियंत्रणाधीन कार्यरत समस्त निगमों को साफ्टवेयर विकास, मैनपावर आपूर्ति एवं स्टार्टअप हेतु इच्छुक प्रतिष्ठित संस्थाओं को सूचीबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में एकरूपता के आधार पर गाईडलाइन्स तैयार कर शासन को प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

निर्देशानुसार निगमों द्वारा विचार-विमर्श करके साफ्टवेयर विकास, मैनपावर आपूर्ति एवं स्टार्टअप हेतु संस्थाओं को सूचीबद्ध (Empanelment) किये जाने विषयक गाईडलाइन्स तैयार की गयी है जिसकी प्रति इस पत्र के साथ क्रमशः संलग्नक-1, संलग्नक-2 एवं संलग्नक-3 पर दृष्टव्य है।

शासन कृपया अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

(प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव)	(डा0 राकेश कुमार वर्मा)	(कुमार प्रशान्त)
प्रबन्ध निदेशक	प्रबन्ध निदेशक	प्रबन्ध निदेशक
यूपीडेस्को	श्रीट्रान एवं अपट्रान पावरट्रानिक्स	यूपीएलसी

कम्प्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की क्रय/विक्रय हेतु प्रक्रिया का निर्धारण

1. एप्लीकेशन साफ्टवेयर हेतु प्रक्रिया:— राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की विभागीय आवश्यकतानुसार एप्लीकेशन साफ्टवेयर के विकास एवं स्थापना के लिए राज्य सरकार के निगमों यथा यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि0, यूपीडेस्को, श्रीट्रॉन इण्डिया लि0 एवं अपट्रॉन पॉवरट्रानिक्स लि0 द्वारा प्रतिष्ठित/राष्ट्रीय आई0टी0 संस्थाओं/कम्पनियों को उनकी कार्य कुशलता, कार्य अनुभव एवं गुणवत्ता के आधार पर सूचीबद्ध किया जाये। निगमों द्वारा आई0टी0 संस्थाओं/कम्पनियों को सूचीबद्ध करने के लिए निम्न मानकों के आधार पर श्रेणीवार सूचीबद्ध किया जाना होगा:—

(क) पंजीकृत संस्थाओं/कम्पनियों जो कम्पनीज एक्ट 1956/2013 अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में पंजीकृत हों एवं इन संस्थाओं/कम्पनियों का देश के किसी राज्य में पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए।

(ख) संस्थाओं/कम्पनियों के मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में साफ्टवेयर एवं तत्सम्बन्धी कार्य करने हेतु प्राविधान हो।

(ग) संस्थाओं/कम्पनियों के पेरोल पर साफ्टवेयर सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न कराए जाने हेतु अनुभवी तकनीकी जनशक्ति के साथ उपयुक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए।

(घ) संस्थाओं/कम्पनियों का पेन (PAN) तथा जी0एस0टी0 (GST) में पंजीकरण होना चाहिए तथा संस्थायें/कम्पनियाँ वित्तीय लाभ की स्थिति में होनी चाहिए। नियमित इनकम टैक्स रिटर्न जमा किया जाना चाहिए।

(ङ) संस्थाओं/कम्पनियों को साफ्टवेयर विकास तथा अन्य कार्यों जिसके लिए वह सूचीबद्ध होना चाहती हैं, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों में सम्बन्धित कार्यो का अच्छा अनुभव होना आवश्यक है।

(च) संस्थाओं/कम्पनियों को भारत के किसी भी प्रदेश अथवा विभाग द्वारा काली सूची में न डाला गया हो तथा संस्था/कम्पनी के निदेशक के विरूद्ध किसी भी न्यायालय अथवा थाने में किसी प्रकार का कोई मुकदमा पंजीकृत न हो।

(छ) आई0एस0ओ0 अथवा सी0एम0एम0आई0 प्रमाणित कम्पनियों/संस्थाओं को वरीयता दी जाए।

(A) Bid Security (Refundable):-

Bidders shall submit/upload, along with their Bids, Bid security of a sum, as mentioned below for Service Provider Category applied for :-

For Service Provider Category "A" → Rs. 2,00,000/- (Rupees Two Lacs only)
For Service Provider Category "B" → Rs. 3,00,000/- (Rupees Three Lacs only)
For Service Provider Category "C" → Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lacs only)

(B) Bid Processing Fee (Non Refundable) :-

For Each Category Rs. 30,000.00 +GST as applicable

(C) Categorization of Service Providers:-

The service providers shall be categorized into the following three categories based on their financial and technical capability, infrastructure available with them

a. Service providers competent to provide services with an estimated project value up to Rs 25 lakhs for the specific job category/ categories --**Category –'A'**.

b. Service providers competent to provide services with an estimated project value up to Rs. 75 lakhs --**Category –'B'**.

c. Service providers competent to provide services with an estimated project value more than Rs 75 lakhs --**Category –'C'**

19

सन्दर्भः यूपीएलसी:साफ्टवेयर:मैनपावर:स्टार्टअप/2018-19

दिनाँकः 18 फरवरी, 2019

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव
आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

महोदय,

दिनाँक 13 फरवरी, 2019 को आहूत समीक्षा बैठक में आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन के नियंत्रणाधीन कार्यरत समस्त निगमों को साफ्टवेयर विकास, मैनपावर आपूर्ति एवं स्टार्टअप हेतु इच्छुक प्रतिष्ठित संस्थाओं को सूचीबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में एकरूपता के आधार पर गाईडलाइन्स तैयार कर शासन को प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

निर्देशानुसार निगमों द्वारा विचार-विमर्श करके साफ्टवेयर विकास, मैनपावर आपूर्ति एवं स्टार्टअप हेतु संस्थाओं को सूचीबद्ध (Empanelment) किये जाने विषयक गाईडलाइन्स तैयार की गयी है जिसकी प्रति इस पत्र के साथ क्रमशः संलग्नक-1, संलग्नक-2 एवं संलग्नक-3 पर दृष्टव्य है।

शासन कृपया अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

(प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव)
प्रबन्ध निदेशक
यूपीडेस्को

(डा0 राकेश कुमार वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक
श्रीट्रान एवं अपट्रान पावरट्रानिक्स

(कुमार प्रशान्त)
प्रबन्ध निदेशक
यूपीएलसी

18

सन्दर्भः यूपीएलसीःसाफ्टवेयरःमैनपावरःस्टार्टअप/2018-19 दिनाँकः फरवरी, 2019

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव
आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

महोदय,

दिनाँक 13 फरवरी, 2019 को आहूत समीक्षा बैठक में आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन के नियंत्रणाधीन कार्यरत समस्त निगमों को साफ्टवेयर विकास, मैनपावर आपूर्ति एवं स्टार्टअप हेतु इच्छुक प्रतिष्ठित संस्थाओं को सूचीबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में एकरूपता के आधार पर गाईडलाइन्स तैयार कर शासन को प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

निर्देशानुसार निगमों द्वारा विचार-विमर्श करके साफ्टवेयर विकास, मैनपावर आपूर्ति एवं स्टार्टअप हेतु संस्थाओं को सूचीबद्ध (Empanelment) किये जाने विषयक गाईडलाइन्स तैयार की गयी है जिसकी प्रति इस पत्र के साथ क्रमशः संलग्नक-1, संलग्नक-2 एवं संलग्नक-3 पर दृष्टव्य है।

शासन कृपया अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

(प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव)
प्रबन्ध निदेशक
यूपीडेस्को

(डा0 राकेश कुमार वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक
श्रीट्रान एवं अपट्रान पावरट्रानिक्स

(कुमार प्रशान्त)
प्रबन्ध निदेशक
यूपीएलसी

d. **Service providers shall have to bid for Empanelment in any One (01) of the above three Categories of the Service Provider (A or B or C).**

(D) Essential Requirements and Experience (as on last date of bid submission)

a) Service Providers competent to provide services with an estimated value up to Rs 25 lakhs -- **Category –'A'.**

Service Provider Company/ Organization:

(1) Should be at least one year old. Audited Balance Sheet and Profit/Loss Account for preceding 01 financial year. Annual Turnover should be minimum Rs. 50 Lakhs.
(2) Income Tax Return (ITR) for the preceding 01 financial year.
(3) Should have at least a LAN installed with 5 desktops/Laptops and one server, one printer and UPS of adequate capacity.
(4) At least two jobs should have been completed successfully of minimum value of Rs 5 lakhs each for each specific Job Category/Categories applied for the Empanelment, during preceding 1 financial year. Job Orders/Awards and their successful Job Completion Certificates are essential. Apart from this, one job order should be in process.
(5) Should have at least 5 permanent employees on rolls for at least one year, out of which at least 3 employees should have recognized B.Tech/B.E. /M.C.A/M.Tech./M.Sc. Degrees, in the areas of Computers/IT/Electronics.

b) Service providers competent to provide services with an estimated value upto Rs. 75 lakhs **Category –'B'.**

Service Provider Company/ Organization:

(1) Should be at least three years old. Audited Balance sheet and Profit/Loss Account for preceding 3 years. Average Annual Turnover of last three financial years should be minimum Rs.5 Cr.
(2) Income Tax Returns (ITRs) for the preceding 03 financial years.
(3) Should have at least a LAN installed with 10 desktops/Laptops and one server, one network printer, scanner and UPS of adequate capacity.
(4) At least three jobs should have been completed successfully of minimum value of Rs 10 lakhs each, during preceding 3 financial years for each Job Category/Categories applied for the Empanelment. Job Orders/Awards and their successful Job Completion Certificates are essential. Apart from this, one job order should be in process.
(5) Should have at least 15 permanent employees on rolls for more than one year, out of which at least 10 employees should have recognized B.Tech/B.E./M.C.A /M.Tech./M.Sc. Degrees, in the areas of Computers/IT/Electronics.
(6) Should have ISO 9000/CMMI Series Certification.

c) Service providers competent to provide services with an estimated value above Rs. 75 lakhs --**Category –'C'.**

Service Provider Company/Organization:

(1) Should be at least Four years old. Audited Balance sheet and Profit/Loss Account for preceding 4 years. Average Annual Turnover of last four years should be minimum Rs.10 Cr.
(2) Income Tax Returns (ITRs) for the preceding 04 financial years.
(3) Should have at least a LAN installed with 20 desktops/Laptops and one server, one network printer, scanner and UPS of adequate capacity.
(4) At least three jobs should have been completed successfully of minimum value of Rs. 50 lakhs each, during preceding 04 financial years for each Job Category/Categories applied for the Empanelment. Job Orders /Awards and their successful Job Completion Certificates are essential. Apart from this, one job order should be in process.
(5) Should have at least 30 permanent employees on rolls for more than one year, out of which at least 25 employees should have recognized B.Tech/ B.E./M.C.A/ M.Tech./M.Sc. Degrees, in the areas of Computers/IT/Electronics.
(6) Should have ISO 9000 or CMM Series certification.

CATEGORY WISE JOB DESCRIPTION

1.1 Job Category-I (Software Development)

Execution of order under this category will be in general, consist of the following steps of operations as per the requirement of individual orders:

a) Preparation of Business Processing Diagram (BPD) or proposal on the basis of preliminary study
b) System Requirement Specifications (SRS)
c) System Design and Development (SDD)
d) Development of the Application Software and website.
e)Testing and Maintenance of the Software and website
f) Application Software to be operated over the Existing Network with modifications.
g) Data Entry and Processing related to Software Developed.
h) Operation and maintenance under warranty period for minimum one year.
i) Operational Manual in two copies, one for the Client Department and other for UPLC.
j) Submission of copies of the Application Developed in Softcopy and hardcopy, User Manual, Design Documents.
k) Deployment of Manpower at Client's site for running the Application Software System
l) Conduct training programs for deployed Application Software.
m) Annual Maintenance of Application Software

1.2 Job Category-II (IT Enabled Services)

Execution of order under this category may consist of one or more of the following jobs:-

Projects like Scanning, Storing, Retrieval and all other aspects of Digitization process, Geographical Interface System (GIS), Survey based development of Application Software, Geo Positioning System (GPS) based tracking system, Records/Document Management Systems/ Storage, smart card/RFID support based application, Services/Solutions of Call Center.

Execution of order under this category will be in general, consist of the following steps of operations as per the requirement of individual orders:

a) Preparation of Business Processing Diagram (BPD) or proposal on the basis of preliminary study.
b) System Requirement Specifications (SRS)
c) System Design and Development (SDD)
d) Development of the Software
e) Testing and Maintenance of the Software
f) Data Entry and Processing related to Software Developed
g) Installation of Hardware, Software and Networking at site. The hardware required for the project shall be procured for the department(s) by the Service Provider as per hardware procurement policy of U.P. Government/UPLC)
h) Submission of copies of the Application Developed in Softcopy and hardcopy, User Manual, Design Documents.
i) Manpower deployment at Client's site for running the system.
j) Conduct training programs for deployed Application Software.
k) Scanning Indexing and digitization of records.

1.3 Job Category-III (Hiring Web / Cloud Server Services on rental Basis)

Execution of order under this category may consist of the following steps of operations. The Service provider in this field of thing web/ Cloud Services on the rental basis for providing server services for U.P. Govt. Departments. The required for the project shall be procured for the department(s) by the service provider as per procurement policy of U.P. Government/UPLC

1. Software as a Service (SaaS)
2. Infrastructure as a Service (IaaS)
3. Platform as a Service (PaaS)
4. Disaster Recovery as a Service (DRaaS)
5. Dev / Test Environment as a Service (DevOps)
6. Virtual Desktops as a Service (VDaaS)
7. Support on all of the above

1.3.1 The Data Center

General Conditions

1. The Data Center and the Data Recovery Center should be located in India
2. The Data Center should be at least Tier III Data Center certified by TIA
3. The Data Center and DRC should be compliant to all ISO standards for DC procedures and Security
4. The data Center should meet the evolving requirements specified in CERT-IN
5. The Data Center should be STQC audited
6. The Data Center should have minimum security application installed including Anti-Virus, Virtual Firewall, Vulnerability identification and protection, Virtual Private Network, SSL, DDOS protection, Data Security and Encryption etc.
7. The DC and DRC should be located in different Seismic Zones
8. Should comply with all IT Security Policies defined/ Imposed by Government of UP and Government of India

1.3.2 System Conditions

1. The Data Center should have all the Hardware and Middleware Infrastructure updated with latest patches and upgrades.
2. All CPUs should be on 64 bit operation with minimum 2.6 GHz speed
3. The Lan and WAN infrastructure should be redundant
4. The VMs should be possibly be deployed in multiple Security Zones as per the requirement of the User Department
5. All possible OS with latest versions/patches should be made available on Hired VMs as per the requirement of User Department
6. Multiple VM and clustering should be made available on demand to User Department
7. Shall be able to provide scalable, redundant, dynamic storage
8. Both Software and Hardware Load Balancer should be available which may be deployed in shared or dedicated mode as per requirement of User Department
9. The VMs should be configured as per requirement of the User Department with minimum configuration with 1GB RAM and 50 GB Storage
10. The shared storage should be made available over AN or NAS as per requirement of the User Department
11. All major Databases such as MS SQL Server, Oracle, DB2, MySQL, PostgreSQL, MongoDB etc. with latest versions/patches should be made available on demand as Infra or as a Service.

1.3.3 User Conditions

The Service Provider should

1. Agree to SLA with 99.5% Uptime measured at VM and Storage level
2. Provide a Hel Desk and Technical Support Services round the clock – 365 days.
3. Provide a VPN connection to the User Department
4. Provide the User Department or their authorized SI a privileged access to VMs and Storage for Management of the Applications
5. Provide facility to manage the VMs through a Web Interface as well as using APIs
6. Maintain the privacy and security of complete data and applications loaded by the User Department or their authorized SI
7. Provide all required tools to maintain he Backup and Recovery policy of the User Department
8. Transfer all the data to the User Department designated Infrastructure after completion of the Contract without any financial implications and make sure to delete all the data from the Cloud which cannot be recovered by any mechanism / tools
9. Provide a Dashboard to the User Department provisioning a comprehensive and detailed view for the health/usage of all hired resources
10. User department should be able to view current/ historic performance of all the VMs
11. Provide alerts on critical health/usage of resources on SMS to designated User Department contacts.

Eligibility Criteria for Category - "A" Service Provider (Software)

A. Pre Qualification

Sl. NO.	Eligibility Criteria	Documents required
1	Company should be registered under Companies Act 1956/2013 or Society Registration Act 1860 from the last minimum one year	Copy of Registration Certificate (Self Certified)
2	Memorandum and Article of Association (Must have mention that execution of Software related work is allowed)	Copy of Memorandum and Article of Association (Self Certified)
3	GST Certificate	Copy of Certificate
4	PAN Certificate	Copy of Certificate
5	ITR for last One financial year	Copy of ITR
6	Positive net worth of last Financial year	Duly Signed Copy of CA Certificate
7	Details of Hardware Infrastructure (Specification and no. of Scanner, Laptop, Printer, Server, UPS etc)	Enclose Separate Sheet (As Per Eligibility Criteria)
8	The Company should not be blacklisted by Central Govt/State Govt/PSU/ Autonomous body in India.	Declaration/Notarize affidavit on Rs 100 Non Judicial Stamp paper

B. Technical qualification

Sl. NO.	Eligibility Criteria	Documents required	Full Marks
1	Company turnover for last Financial year Rs 50 Lacs <=70 Lacs → 5 Marks >Rs 70 Lacs <=90 Lacs → 10 Marks >Rs 90 Lacs <=110 Lacs → 15 Marks >Rs 110 Lacs → 20 Marks	Duly Signed Copy of CA Certificate and Copy of Balance sheet and P/L Account	20
2	Company should have executed projects for Central Govt./State Govt. / PSU/ other Govt. Institution having minimum value of Rs. 5 Lacs or above 2 Projects → 15 Marks 3 Projects → 20 Marks 4 Projects → 25 Marks 5 Projects or above →30 Marks	Copy of work Order (Self Certified)	30
3	Company should submit at least one running work order of minimum value of Rs. 5 lacs for Central Govt/State Govt/PSU/ other Government Institution.	Copy of work Order (Self Certified)	15
4	Company should have ISO or CMMI Certification ISO 9001:2008 or CMMI Level 3 → 10 Marks, ISO 27001:2013 or CMMI Level 5 → 15 Marks	ISO or CMMI Level Certificate	15
5	Company should have 5 manpower on Roll for project handling out of which at least 3 Technical staff must have (MCA/B.Tech/BE/ M.Tech/ M.Sc.IT) < 05 --0 Marks 05 to 10 -- 5 Marks 11 to 15 -- 10 Marks 16 to 20 -- 15 Marks Above 20 -- 20 Marks	HR Certificate on letter head	20
	Total Marks		**100**

Minimum Qualifying Marks: 60*

Eligibility Criteria for Category - "B" Service Provider (Software)

A. Pre Qualification

Sl. NO.	Eligibility Criteria	Documents required
1	Company should be registered under Companies Act 1956/2013 or Society Registration Act 1860 from the last minimum three years	Copy of Registration Certificate (Self Certified)
2	Memorandum and Article of Association (Must have mention that execution of Software related work is allowed)	Copy of Memorandum and Article of Association (Self Certified)
3	GST Certificate	Copy of Certificate
4	PAN Certificate	Copy of Certificate
5	ITR for last three financial years	Copy of ITRs
6	Positive net worth of last Financial year	Duly Signed Copy of CA Certificate
7	Details of Hardware Infrastructure (Specification and no. of Scanner, Laptop, Printer, Server, UPS etc)	Enclose Separate Sheet (As Per Eligibility Criteria)
8	The Company should not be blacklisted by Central Govt/State Govt/PSU/ Autonomous body in India.	Declaration/Notarize affidavit on Rs 100 Non Judicial Stamp paper

B. Technical Qualification

Sl. NO.	Eligibility Criteria	Documents required	Full Marks
1	Company average annual turnover for last 3 Financial years Rs 5 Cr <= 7 Cr → 5 Marks >Rs 7 Cr <= 10 Cr → 10 Marks >Rs 10 Cr <= 15 Cr →15 Marks >Rs 15 Cr → 20 Marks	Duly Signed Copy of CA Certificate and Copy of Balance sheet and P/L Account	20
2	Company should have executed projects for Central Govt/State Govt. / PSU/ other Govt. Institution having minimum value of Rs. 10 Lacs or above 3 Projects → 20 Marks 4 Projects → 25 Marks 5 Projects or above →30 Marks	Copy of work Order (Self Certified)	30
3	Company should submit at least one running work order of minimum value of Rs. 10 lacs for any Central Govt/State Govt/PSU/ other Government Institution.	Copy of work Order (Self Certified)	15
4	Company's should have ISO or CMMI Certification ISO 9001:2008 or CMMI Level 3 → 10 Marks, ISO 27001:2013 or CMMI Level 5 → 15 Marks	ISO or CMMI Level Certificate	15
5	Company should have 15 manpower on Roll for project handling out of which at least 10 Technical staff must have (MCA/B.Tech/B.E/ M.Tech/ M.Sc.IT) < 15 --0 Marks 15 to 25 -- 5 Marks 26 to 35 -- 10 Marks 36 to 45 -- 15 Marks Above to 45 -- 20 Marks	HR Certificate on letter head	20
	Total Marks		**100**

Minimum Qualifying Marks: 60

Eligibility Criteria for Category - "C" Service Provider (Software)

A. Pre Qualification

Sl. NO.	Eligibility Criteria	Documents required
1	Company should be registered under Companies Act 1956/2013 or Society Registration Act 1860 from the last minimum four years	Copy of Registration Certificate (Self Certified)
2	Memorandum and Article of Association (Must have mention that execution of Software related work is allowed)	Copy of Memorandum and Article of Association (Self Certified)
3	GST Certificate	Copy of Certificate
4	PAN Certificate	Copy of Certificate
5	ITR for last four financial years	Copy of ITRs
6	Positive net worth of last Financial year	Duly Signed Copy of CA Certificate
7	Details of Hardware Infrastructure (Specification and no. of Scanner, Laptop, Printer, Server, UPS etc)	Enclose Separate Sheet (As Per Eligibility Criteria)
8	The Company should not be blacklisted by Central Govt/State Govt/PSU/ Autonomous body in India.	Declaration/Notarize affidavit on Rs 100 Non Judicial Stamp paper

B. Technical Qualification

Sl. NO.	Eligibility Criteria	Documents required	Full Marks
1	Company average annual turnover for last 4 Financial years Rs 10 Cr <= 15 Cr → 5 Marks >Rs 15 Cr <= 20 Cr → 10 Marks >Rs 20 Cr <= 25 Cr → 15 Marks >Rs 25 Cr → 20 Marks	Duly Signed Copy of CA Certificate and Copy of Balance sheet and P/L Account	20
2	Company should have executed projects for Central govt/ State Govt. / PSU/ other Govt. Institution having minimum value of Rs 50 Lacs or above 3 Projects →20 Marks 4 Projects → 25 Marks 5 Projects or above →30 Marks	Copy of work Order (Self Certified)	30
3	Company should submit at least one running work order of minimum value of Rs 50 lacs of any Central Govt/State Govt/PSU/ other Government Institution.	Copy of work Order (Self Certified)	15
4	Company's should be ISO or CMMI Certification ISO 9001:2008 or CMMI Level 3 → 10 Marks, ISO 27001:2013 or CMMI Level 5 → 15 Marks	ISO or CMMI Level Certificate	15
5	Company should have 30 manpower on Roll for project handling out of which 25 Technical staff must have (MCA/B-Tech/B.E/ M-Tech/ M.Sc. IT) < 30 --0 Marks 30 to 40 -- 5 Marks 41 to 50 -- 10 Marks 51 to 60 -- 15 Marks Above 60 -- 20 Marks	HR Certificate on letter head	20
	Total Marks		**100**

Minimum Qualifying Marks: 60

प्रत्येक निगम द्वारा उपरोक्तानुसार साफ्टवेयर एवं अन्य सेवाओं से सम्बन्धित संस्थाओं/कम्पनियों के इम्पैनलमेन्ट की कार्यवाही हेतु किसी विशेष स्पेशलाइज़ेशन/प्रोजेक्ट वैल्यू के स्थान पर उपरोक्त व्यवस्थानुसार प्रत्येक प्रकार के कार्यों/कार्य वैल्यू हेतु इम्पैनलमेन्ट की कार्यवाही की जाये। इससे विभागों के पास किसी विशेष प्रकार के कार्यों को किसी भी निगम से कराये जाने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था भी रहेगी तथा साथ ही उनको कॉम्पटीटिव दरें भी प्राप्त हो सकेंगी। उक्तानुसार व्यवस्था से निगमों के व्यावसायिक हित भी प्रभावित नहीं होगें।

निगमों में इम्पैलमेन्ट हेतु अर्हतानुसार प्रत्येक संस्था/कम्पनी को प्रत्येक निगम की प्रक्रिया में भाग लेने की छूट हो। एक संस्था/कम्पनी के केवल एक निगम में इम्पैनल होने की व्यवस्था लागू करने में, सम्बन्धित निगम को इम्पैनमेन्ट के समय एक ओर तो अन्य निगमों में इम्पैनलड संस्थाओं/कम्पनियों की सूची को औपचारिक रूप से मंगाकर संज्ञान में लेना होगा वहीं दूसरी ओर ऐसी संस्थाओं/कम्पनियों जो अन्य किसी निगम में इम्पैनल हो चुकी हों, को अपने निगम में उक्त कारण से इम्पैनल नहीं करने पर वैधानिक अड़चने आ सकती हैं। उक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित निगमों द्वारा विभागीयों कार्यों के लिए प्रकाशित की जाने वाली निविदाओं में उनके यहाँ उपयुक्त संस्थाओं/कम्पनियों के इम्पैनल नहीं होने के कारण कॉम्पटीटिव दरें प्रभावित होने की सम्भावना रहेगी। अतः यह उचित होगा कि कोई भी निविदादाता संस्था किन्हीं दो निगमों में ही सूचीबद्ध हो सकती है।

निगमों द्वारा उपरोक्तानुसार आई0टी0 कम्पनियों को उनकी कार्य कुशलता, गुणवत्ता एवं कार्य अनुभव के अनुसार श्रेणीवार सूचीबद्ध किया जायेगा।

उपरोक्त के क्रम में यह आवश्यक होगा कि आई0टी0 विभाग के नियंत्रणाधीन चारों निगमों यथा यूपीएलसी, यूपीडेस्को, श्रीट्रॉन इण्डिया लि. एवं अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लि. द्वारा एक वर्ष में केवल एक ही बार आई0टी0 कम्पनियों/संस्थाओं को सूचीबद्ध किये जाने हेतु ई–निविदा प्रकाशित की जायेगी जिसकी निविदा सूचना (Tender Notice) राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर के दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित अवश्य की जायेगी। उक्त निगमों को यह प्रक्रिया अधिकतम 3 माह में निम्नानुसार पूर्ण किया जायेगा।

1.	यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन	–	जनवरी से मार्च तक
2.	श्रीट्रॉन इण्डिया लि.	–	अप्रैल से जून तक
3.	अपट्रॉन पॉवरट्रानिक्स लि.	–	जुलाई से सितम्बर तक
4.	यूपीडेस्को	–	अक्टूबर से दिसम्बर तक

उक्त के अतिरिक्त शासकीय विभागों/संस्थाओं द्वारा यदि एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय विकास से सम्बन्धित कार्य आई0टी0 इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रणाधीन उक्त निगमों को आबंटित किया जाता है तो उक्त निगमों द्वारा एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय/विकास का कार्य उनके द्वारा सूचीबद्ध की गई कम्पनियों से कराये जाने हेतु उनसे तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त किये जाने हेतु केवल ई–निविदा के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया का उपयोग आवश्यक है।

उक्त के क्रम में शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा आई0टी0 विभाग के उक्त निगमों के माध्यम से यदि एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय/विकास अथवा अन्य सम्बन्धित कार्य कराया जाता है तो उसके लिए निगमों द्वारा निम्न प्रक्रियानुसार सूचीबद्ध संस्थाओं में से किसी एक न्यूनतम निविदादाता संस्था/कार्यदायी संस्था का चयन उक्त कार्य हेतु किया जायेगाः–

(क). शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से कार्य प्राप्त होने के उपरान्त निगमों द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाएगा जिसमें एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय/विकास कार्य हेतु स्कोप ऑफ वर्क स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। तदोपरान्त सूचीबद्ध संस्थाओं को स्कोप ऑफ वर्क उपलब्ध कराते हुए उनसे कार्य

हेतु ई–निविदा के माध्यम से वित्तीय प्रस्ताव/कोटेशन प्राप्त किए जाऐंगे। निविदा में तकनीकी एवं वित्तीय बिड का प्राविधान रखा जायेगा।

(ख). उक्त कोटेशन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होगा कि निगमों में कार्य श्रेणी के अनुसार सूचीबद्ध संस्थाओं को स्कोप ऑफ वर्क उपलब्ध कराते हुए निविदा तैयार की जाए तथा निविदा ई–पोर्टल पर प्रकाशित किया जाए। निविदा प्रक्रिया से वित्तीय प्रस्ताव/कोटेशन निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त किए जाएंगे तथा तकनीकी रूप से अंर्ह पायी गई निविदाओं के वित्तीय प्रस्ताव/कोटेशन होने पर ही समिति के समक्ष उनके प्रस्ताव खोले जाएंगे।

(ग). जिस भी संस्था का वित्तीय प्रस्ताव न्यूनतम होगा उसी संस्था को कार्याबंटित किया जाएगा।

(घ). उक्त हेतु निगम स्तर पर अधिक सुस्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करते हुए नियमों को विस्तृत प्रक्रिया निगम स्तर पर तैयार करनी होगी जिसमे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस भी सूचीबद्ध संस्था को कार्य आबंटित हो उसकी प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी हो तथा संस्था का चयन न्यूनतम बिड मूल्य के आधार पर हो।

सलग्नक-2 09

जनशक्ति आपूर्ति हेतु प्रक्रिया का निर्धारण

1. **उपयुक्त जनशक्ति हेतु प्रक्रिया:–** राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य सम्पादन/संचालन हेतु उपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य सरकार के निगमों यथा यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि0, यूपीडेस्को, श्रीट्रॉन इण्डिया लि. एवं अपट्रॉन पॉवरट्रानिक्स लि. द्वारा प्रतिष्ठित/राष्ट्रीय संस्थाओं/कम्पनियों को उनकी कार्य कुशलता, कार्य अनुभव एवं गुणवत्ता के आधार पर सूचीबद्ध किया जाये। निगमों द्वारा संस्थाओं/कम्पनियों को सूचीबद्ध करने के लिए निम्न मानको के आधार पर श्रेणीवार सूचीबद्ध किया जाना होगा:–

(क) पंजीकृत संस्थाओं/कम्पनियों जो कम्पनीज एक्ट 1956/2013 अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में पंजीकृत हों एवं इन संस्थाओं/कम्पनियों का देश के किसी राज्य में पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए।

(ख) संस्थाओं/कम्पनियों के मेमोरेन्डम एण्ड आर्टकिल्स ऑफ एसोसिएशन में जनशक्ति उपलब्ध कराने सम्बन्धी कार्य करने हेतु प्राविधान हो।

(ग) संस्थाओं/कम्पनियों के पेरोल पर जनशक्ति सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न कराये जाने हेतु अनुभवी जनशक्ति के साथ उपयुक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए।

(घ) संस्थाओं/कम्पनियों का पेन (PAN) तथा जी0एस0टी0 (GST), EPF तथा ESI के साथ–साथ श्रम विभाग में पंजीकृत होना चाहिए तथा कम्पनियाँ वित्तीय लाभ की स्थिति में होना चाहिएं। नियमित इनकम टैक्स रिटर्न जमा किया जाना चाहिए।

(ड़) संस्थाओं/कम्पनियों को जनशक्ति सम्बन्धी कार्यों जिसके लिए वह सूचीबद्ध होना चाहती है, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों में सम्बन्धित कार्यो का अच्छा अनुभव होना आवश्यक है।

(च) संस्थाओं/कम्पनियों को भारत के किसी भी प्रदेश अथवा विभाग द्वारा काली सूची में न डाला गया हो तथा कम्पनी के निदेशक के विरूद्ध किसी भी न्यायालय अथवा थाने में किसी प्रकार का कोई मुकदमा पंजीकृत न हो।

A. Bid Security(Refundable):-

Bidders shall submit/upload, along with their Bids, Bid security of a sum, as mentioned below for Outsource Agency Category applied for:-

For Outsource Agency Category "A" → Rs. 2,00,000/- (Rupees Two Lacs only)
For Outsource Agency Category "B" → Rs. 3,00,000/- (Rupees Three Lacs only)
For Outsource Agency Category "C" → Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lacs only)

B. Bid Processing Fee (Non Refundable):-

- For each Category Rs. 30,000.00 + GST as applicable

C. Categorization of Outsource Agency

The Outsource Agency shall be categorized into the following Three categories based on their financial and technical capability, infrastructure available with them

1.1 Categories

a. Outsource Agency competent to provide services with an estimated project value up to Rs 25 lakhs for the specific job category/ categories --**Category –'A'.**

08

b. Outsource Agency competent to provide services with an estimated project value more than Rs 75 lakhs --**Category –'B'.**

c. Outsource Agency competent to provide services with an estimated project value more than Rs 75 lakhs --**Category –'C'**

1.2 Outsource Agencies shall have to bid for Empanelment in any One (01) of the above 03 Categories of the Outsource Agency (A or B or C).

1.3. Essential Requirements and Experience

Tenderers must fulfil the following requirements and submit the Self certified copies thereof in documentary support with the tender

2.1 Outsource Agency competent to provide services with an estimated value up to Rs 25 lakhs -- Category –'A'.

Outsource Agency:

a. The Agency must be a Company / registered under Companies Act 1956/2013 or Society Registration Act 1860 and should be in existence for a minimum of one year.
b. The Agency should have a minimum annual turnover of at-least Rs. 50,00,000/-(Fifty Lakhs) in the last financial year.
c. Valid E.S.I, Provident Fund, PAN, GST Registration Number in the name of agency.
d. Valid registration in Labour Department.
e. Annual Income Tax paid exceeding Rs. 30,000/- in last financial year.
f. Audited/Certified Balance sheets and P/L of the preceding financial year.
g. Income Tax Returns (ITRs) for last financial year.
h. Should have completed successfully at least two jobs of minimum value of Rs. 5 lakhs each, and successful Job completion certificates are essential.

2.2 Outsource Agency competent to provide services with an estimated value up to Rs. 75 lakhs

-- Category –'B'.

Outsource Agency:

a. The Agency must be a Company / registered under Companies Act 1956/2013 or Society Registration Act 1860 and should be in existence for a minimum of three years.
b. The Agency should have a minimum annual turnover of at-least Rs. 2,00,00,000/- (Two Crores) in each of the last three financial years.
c. Valid E.S.I, Provident Fund, PAN, GST Registration Number in the name of agency.
d. Valid registration in Labour Department.
e. Average Annual Income Tax paid exceeding Rs. 50,000/- in last three assessment years.
f. Audited/Certified Balance sheets and P/L for the preceding 03 financial years.
g. Income Tax Returns (ITRs) for the preceding 03 financial years.
h. Should have completed successfully at least three jobs of minimum value of Rs. 10 lakhs each, and successful Job completion certificates are essential.

07

2.3 Outsource Agency competent to provide services with an estimated value more than Rs. 75 lakhs -- category –'C'.

Outsource Agency:

a. The Agency must be a Company / registered under Companies Act 1956/2013 or Society Registration Act 1860 and should be in existence for a minimum of four years.

b. The Agency should have a minimum annual turnover of at-least Rs. 5,00,00,000/- (Five Crores) in each of the last four financial years.

c. Valid E.S.I, Provident Fund, PAN, GST Registration Number in the name of agency.

d. Valid registration in Labour Department.

e. Average Annual Income Tax paid exceeding Rs. 1,00,000/- in last four assessment years.

f. Audited/Certified Balance sheets and P/L for the preceding 04 financial years.

g. Income Tax Returns (ITRs) for the preceding 04 financial years.

h. Should have completed successfully at least four jobs of minimum value of Rs. 25 lakhs each, and successful Job completion certificates are essential.

2.4. Tenderers must enclose following documents:-

a. An affidavit duly notarized by Notary mentioning that-

i. The Tenderer has never been black listed by any Government Department and convicted by any Court of Law and there has been no litigation with any Government Department on account of similar services.

ii. There is no Police case/ Court case/ Vigilance inquiry/ Labour dispute/ Tax Recovery Case pending against the tender firm or its Directors/ CEO/Partners.

iii. Tenderer has never been a defaulter in filing timely returns of E.S.I and Income Tax & Service Tax/GST in last one/three/four financial years for Categories A/B/C respectively.

iv. Tenderer will deposit ESI, PF, Income Tax and GST in time.

v. Tenderer has good record in past. No action has been taken by any authority with whom, the tenderer has undergone contract as Outsource Agency.

b. All attested copies of annual returns, as the case may be filled by the tenderer in last one/three/four years for Categories A/B/C respectively with regard to ESI, PF, Income Tax & Service Tax/GST.

c. Relevant Experience in the field/Contract Copies and Certificate issued by two or more concerned authorities with whom the tender have delivered manpower successfully during last three years in any Government Department or any Centre/State, World Bank funded Projects or Public Sector Units or Government Societies.

Eligibility Criteria for Category - "A" for Outsource Agency

A. Pre Qualification

Sl. NO.	Eligibility Criteria	Documents required
1	Company should be registered under Companies Act 1956/2013 or Society Registration Act 1860 from the last minimum one year	Copy of Registration Certificate (Self Certified)
2	Memorandum and Article of Association (Must have mention that execution of Software related work is allowed)	Copy of Memorandum and Article of Association (Self Certified)
3	GST Certificate	Copy of Certificate
4	PAN Certificate	Copy of Certificate
5	ITR for last financial year	Copy of ITRs
6	Positive net worth of last Financial year	Duly Signed Copy of CA Certificate
7	E.S.I, Provident Fund statements	Copy of Certificate
8	Proof of registration in Labour Department.	Copy of Certificate
9	The Company should not be blacklisted by Central Govt/State Govt/PSU/ Autonomous body in India.	Declaration/Notarize affidavit on Rs 100 Non Judicial Stamp paper

B. Technical Qualification

Sl. NO.	Eligibility Criteria	Documents required	Full Marks
1	Company turnover for last Financial year Below 50 Lacs →0 Marks >Rs 50 Lacs <=70 Lacs → 10 Marks Rs 70 Lacs <= 90 Lacs → 15 Marks Rs 90 Lacs <= 110 Lacs → 20 Marks Rs 110 Lacs → 25 Marks	Duly Signed Copy of CA Certificate and Copy of Balance sheet and P/L Account	25
2	Bidder should have executed projects for Central Govt/State Govt. / PSU/ other Govt. Institution having minimum value of Rupee 5 Lacs or above 2 Projects →10 Marks 3 Projects → 15 Marks 4 Projects or above → 20 Marks	Copy of Work Order	20
3	Company should submit at least one running work order of minimum value of Rs. 5 lacs for Central Govt/State Govt/PSU/ other Government Institution.	Copy of Work Order	15
4	Company should have ISO Certification ISO 9001:2008 → 20 Marks	ISO Certificate	20
5	Bidder should have 5 manpower on Roll for project handling < 5 --0 Marks 05 to 10 -- 5 Marks 11 to 15 -- 10 Marks 16 to 20 -- 15 Marks 21 or Above -- 20 Marks	HR Certificate on letter head	20
	Total Marks		**100**

Minimum Qualifying Marks: 60

Eligibility Criteria for Category - "B" Outsource Agency

A. Pre Qualification

Sl. NO.	Eligibility Criteria	Documents required
1	Company should be registered under Companies Act 1956/2013 or Society Registration Act 1860 from the last minimum three years	Copy of Registration Certificate (Self Certified)
2	Memorandum and Article of Association (Must have mention that execution of Software related work is allowed)	Copy of Memorandum and Article of Association (Self Certified)
3	GST Certificate	Copy of Certificate
4	PAN Certificate	Copy of Certificate
5	ITR for last three financial years	Copy of ITRs
6	Positive net worth of last Financial year	Duly Signed Copy of CA Certificate
7	E.S.I, Provident Fund statements	Copy of Certificate
8	Proof of registration in Labour Department.	Copy of Certificate
9	The Company should not be blacklisted by Central Govt/State Govt/PSU/ Autonomous body in India.	Declaration/Notarize affidavit on Rs 100 Non Judicial Stamp paper

B. Technical Qualification

Sl. NO.	Eligibility Criteria	Documents required	Full Marks
1	Company average annual turnover for last 3 Financial years Below 5 Cr →0 Marks >Rs 05 Cr <=07 Cr → 10 Marks >Rs 07 Cr <= 10 Cr → 15 Marks >Rs 10 Cr <= 15 Cr → 20 Marks >Rs 15 Cr above → 25 Marks	Duly Signed Copy of CA Certificate and Copy of Balance sheet and P/L Account	25
2	Bidder should have executed projects for Central Govt/State Govt. / PSU/ other Govt. Institution having minimum value of Rupee 10 Lacs or above 3 Projects → 15 Marks 4 Projects or above → 20 Marks	Copy of Work Order	20
3	Company should submit at least one running work order of minimum value of Rs. 10 lacs for Central Govt/State Govt/PSU/ other Government Institution.	Copy of Work Order	15
4	Company should have ISO Certification ISO 9001:2008 → 20 Marks	ISO Certificate	20
5	Bidder should have 20 manpower on Roll for project handling < 20 --0 Marks 20 to 30 -- 5 Marks 31 to 40 -- 10 Marks 41 to 50 -- 15 Marks Above 50 -- 20 Marks	HR Certificate on letter head	20
	Total Marks		**100**

Minimum Qualifying Marks: 60

Eligibility Criteria for Category - "C" for Outsource Agency

A. Pre Qualification

Sl. NO.	Eligibility Criteria	Documents required
1	Company should be registered under Companies Act 1956/2013 or Society Registration Act 1860 from the last minimum four years	Copy of Registration Certificate (Self Certified)
2	Memorandum and Article of Association (Must have mention that execution of Software related work is allowed)	Copy of Memorandum and Article of Association (Self Certified)
3	GST Certificate	Copy of Certificate
4	PAN Certificate	Copy of Certificate
5	ITR for last four financial years	Copy of ITRs
6	Positive net worth of last Financial year	Duly Signed Copy of CA Certificate
7	E.S.I, Provident Fund statements	Copy of Certificate
8	Proof of registration in Labour Department.	Copy of Certificate
9	The Company should not be blacklisted by Central Govt/State Govt/PSU/ Autonomous body in India.	Declaration/Notarize affidavit on Rs 100 Non Judicial Stamp paper

B. Technical Qualification

Sl. NO.	Eligibility Criteria	Documents required	Full Marks
1	Company average annual turnover for last 04 Financial year Below 5 Cr →0 Marks >Rs 5 Cr <=10 Cr → 10 Marks >Rs 10 Cr <= 20 Cr → 15 Marks >Rs 20 Cr <= 30 Cr → 20 Marks >Rs 30 Cr above → 25 Marks	Duly Signed Copy of CA Certificate and Copy of Balance sheet and P/L Account	25
2	Bidder should have executed projects for Central Govt/State Govt. / PSU/ other Govt. Institution having minimum value of Rupee 25 Lacs or above 3 Projects → 10 Marks 4 Projects or above → 20 Marks	Copy of Work Order	20
3	Company should submit at least one running work order of minimum value of Rs. 05 lacs for Central Govt/State Govt/PSU/ other Government Institution.	Copy of Work Order	15
5	Company should have ISO Certification ISO 9001:2008 → 20 Marks	ISO Certificate	20
6	Bidder should have 30 manpower on Roll for project handling < 30 --0 Marks 31 to 40 -- 5 Marks 41 to 50 -- 10 Marks 51 to 60 -- 15 Marks Above 60 -- 20 Marks	HR Certificate on letter head	20
	Total Marks		**100**

Minimum Qualifying Marks: 60

निगमों द्वारा उपरोक्तानुसार जनशक्ति सेवा प्रदाता संस्थाओं को उनकी कार्यकुशलता, गुणवत्ता एवं कार्य अनुभव के अनुसार श्रेणीवार सूचीबद्ध किया जायेगा।

उपरोक्त के क्रम में यह आवश्यक होगा कि आई0टी0 विभाग के नियंत्रणाधीन चारों निगम यथा यूपीएलसी, यूपीडेस्को, श्रीट्रॉन इण्डिया लि. एवं अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लि. द्वारा एक वर्ष में केवल एक ही बार संस्थाओं/कम्पनियों को सूचीबद्ध किये जाने हेतु ई–निविदा प्रकाशित की जायेगी जिसकी निविदा सूचना (Tender Notice) राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर के दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित अवश्य की जायेगी। उक्त निगमों को यह प्रक्रिया अधिकतम 3 माह में निम्नानुसार पूर्ण किया जायेगा।

1.	यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन	–	जनवरी से मार्च तक
2.	श्रीट्रॉन इण्डिया लि.	–	अप्रैल से जून तक
3.	अपट्रॉन पॉवरट्रानिक्स लि.	–	जुलाई से सितम्बर तक
4.	यूपीडेस्को	–	अक्टूबर से दिसम्बर तक

उक्त के अतिरिक्त शासकीय विभागों/संस्थाओं द्वारा यदि जनशक्ति से सम्बन्धित कार्य आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रणाधीन उक्त निगमों को आबंटित किया जाता है तो उक्त निगमों द्वारा जनशक्ति का कार्य उनके द्वारा सूचीबद्ध की गई कम्पनियों से कराये जाने हेतु उनसे तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त किये जाने हेतु केवल ई–निविदा के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया का प्रयोग आवश्यक है।

उक्त के क्रम में शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा आई0टी0 विभाग के उक्त निगमों के माध्यम से यदि जनशक्ति उपलब्ध कराने का कार्य कराया जाता है तो उसके लिए निगमों द्वारा निम्न प्रक्रियानुसार सूचीबद्ध संस्थाओं में से किसी एक न्यूनतम निविदादाता संस्था/कार्यदायी संस्था का चयन उक्त कार्य हेतु किया जायेगाः–

(क). निगमों को शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से कार्य प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव तैयार किया जाएगा जिसमें जनशक्ति के चयन में सम्बन्धित विभाग की भागीदारी होगी तथा प्रस्तावित जनशक्ति की योग्यता तथा अनुभव की शर्ते भी उनसे विचार विमर्श कर निर्धारित की जायेगी। तदनुसार स्वीकृत स्कोप ऑफ वर्क स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। तदोपरान्त सूचीबद्ध संस्थाओं को स्कोप ऑफ वर्क को उपलब्ध कराते हुए उनसे कार्य हेतु ई–निविदा के माध्यम से वित्तीय प्रस्ताव/कोटेशन प्राप्त किए जाऐंगे। निविदा में तकनीकी एवं वित्तीय बिड का प्राविधान हो।

(ख). उक्त कोटेशन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होगा कि निगमों में समस्त सूचीबद्ध संस्थाओं को स्कोप ऑफ वर्क उपलब्ध कराते हुए निविदा तैयार की जाए तथा निविदा को ई–पोर्टल पर प्रकाशित किया जाए। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त तकनीकी रूप से अंर्ह पायी गई निविदाओं के वित्तीय प्रस्ताव/कोटेशन समिति के समक्ष खोले जाएंगे।

(ग). जिस भी संस्था का वित्तीय प्रस्ताव न्यूनतम होगा उसी संस्था को कार्याबंटित किया जाएगा।

(घ). उक्त हेतु निगम स्तर पर अधिक सुस्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करते हुए नियमों को विस्तृत प्रक्रिया निगम स्तर पर तैयार करनी होगी जिसमे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस भी सूचीबद्ध संस्था को कार्य आबंटित हो उसकी प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी हो तथा संस्था का चयन न्यूनतम बिड मूल्य के आधार पर हो।

(ड). कार्यदायी संस्था द्वारा सम्बन्धित विभाग में सम्बद्ध की जाने वाली जनशक्ति को प्रत्येक माह की सेवाओं उपरान्त प्रत्यके माह में अगले माह के पहले सात दिनों के अन्दर उनके पारिश्रमिक/वेतन का भुगतान करना होगा तथा प्रत्येक माह की 15 तारीख तक ई.एस.आई. तथा ई.पी.एफ. का अंश तथा 20 तारीख तक जीएसटी जमा किया जायेगा। जिसकी प्रतिपूर्ति सम्बन्धित निगम द्वारा विभाग से प्राप्त धनराशि से संस्था द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बीजकों के सापेक्ष किया जायेगा।

Eligibility Criteria for Empanelment of Startup Companies under Category-"S"

Empanelment for Solution Design, Development of Application Software/ Website, Web Based Application, Data Processing, IT/ITES Services and Scanning & Digitization work.

Startup Companies competent to provide services with an estimated value up to Rs. 25 lakhs for a single work.

Eligibility:

(1) Must be registered as Startup Company under DIPP (Department of Industrial Policy & Promotion) Startup program of GoI.
(2) Must be working in any incubation center in India.
(3) The Company should not be blacklisted by Central Govt/State Govt/PSU/ Autonomous body in India.
(4) Should have at least 2 employees on pay rolls.
(5) The Startup owner/founder should be at least a Graduate from recognized University.
(6) The Startup owner/ founder should be a resident of India.
(7) Must have Income Tax (PAN) Registration.
(8) Must have or applied for GST Registration.
(9) Details of Hardware Infrastructure (Specification and no. of Scanner, Laptop, Printer, UPS etc)

A. Pre Qualification

..O.	Eligibility Criteria	Documents required
1	Must be a REGISTERED Start-up Company under DIPP, GoI.	Copy of Registration Certificate (Self Certified)
2	Should have at least 2 employee on rolls	Declaration (Self Certified)
3	The Startup owner/founder should be at least a Graduate from recognized University	Declaration (Self Certified)
4	Must have Income Tax (PAN) Registration.	Copy of Certificate
5	Must have or applied for GST Registration	Copy of Certificate
6	The Company should not be blacklisted by Central Govt/State Govt/PSU/ Autonomous body in India.	Declaration/Notarize affidavit on Rs 100 Non Judicial Stamp paper

B. Technical Qualification

Sl. NO.	Eligibility Criteria	Documents required	Full Marks
	The Start-up owner must have at least 5 project executed at least (one Project/ Service with five clients) or running project for any Institution (Public/ Private Sector) One Project ---10 Two Projects --- 15 Three Projects ----20 Four Projects ----25 Five Projects ----30	Copy of Certificate / work order	30
3	Should have at least 2 employee on rolls Two Employees -- 10 Three Employees --15 More than Three Employees -- 20	Declaration (Self Certified)	20
	Total Marks		**50**

Minimum Qualifying Marks: 25

निविदा प्रोसेसिंग शुल्क रू0 5000/– + जीएसटी तथा ईएमडी/परफॉरमेन्स सिक्योरिटी कोई नहीं होगी।

निगमों द्वारा उपरोक्तानुसार स्टार्ट अप कम्पनियों को उनकी कार्य कुशलता, गुणवत्ता एवं कार्य अनुभव के अनुसार श्रेणीवार सूचीबद्ध किया जायेगा।

उपरोक्त के क्रम में यह आवश्यक होगा कि आई0टी0 विभाग के नियंत्रणाधीन चारों निगमों यथा यूपीएलसी, यूपीडेस्को, श्रीट्रॉन इण्डिया लि. एवं अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लि. द्वारा एक वर्ष में केवल एक ही बार स्टार्ट अप कम्पनियों/संस्थाओं को सूचीबद्ध किये जाने हेतु ई–निविदा प्रकाशित की जायेगी जिसकी निविदा सूचना (Tender Notice) राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर के दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित अवश्य की जायेगी। उक्त निगमों को यह प्रक्रिया अधिकतम 3 माह में निम्नानुसार पूर्ण किया जायेगा।

1.	यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन	–	जनवरी से मार्च तक
2.	श्रीट्रॉन इण्डिया लि.	–	अप्रैल से जून तक
3.	अपट्रॉन पॉवरट्रानिक्स लि.	–	जुलाई से सितम्बर तक
4.	यूपीडेस्को	–	अक्टूबर से दिसम्बर तक

उक्त के अतिरिक्त शासकीय विभागों/संस्थाओं द्वारा यदि उपरोक्त स्कोप ऑफ वर्क से सम्बन्धित कार्य आई0टी0 इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रणाधीन उक्त निगमों को आबंटित किया जाता है तो उक्त निगमों द्वारा उक्त कार्य उनके द्वारा सूचीबद्ध की गई स्टार्ट अप कम्पनियों से कराये जाने हेतु उनसे तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त किये जाने हेतु केवल ई–निविदा के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया का उपयोग आवश्यक है।

उक्त के क्रम में शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा आई0टी0 विभाग के उक्त निगमों के माध्यम से यदि सम्बन्धित कार्य कराया जाता है तो उसके लिए निगमों द्वारा निम्न प्रक्रियानुसार सूचीबद्ध संस्थाओं में से किसी एक न्यूनतम निविदादाता संस्था/कार्यदायी संस्था का चयन उक्त कार्य हेतु किया जायेगा:–

(क). शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से कार्य प्राप्त होने के उपरान्त निगमों द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाएगा जिसमें कार्य हेतु स्कोप ऑफ वर्क स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। तदोपरान्त सूचीबद्ध संस्थाओं को स्कोप ऑफ वर्क उपलब्ध कराते हुए उनसे कार्य हेतु ई–निविदा के माध्यम से वित्तीय प्रस्ताव/कोटेशन प्राप्त किए जाऐंगे। निविदा में तकनीकी एवं वित्तीय बिड का प्राविधान रखा जायेगा।

(ख). उक्त कोटेशन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होगा कि निगमों में स्टार्ट अप श्रेणी में सूचीबद्ध संस्थाओं को स्कोप ऑफ वर्क उपलब्ध कराते हुए निविदा तैयार की जाए तथा निविदा ई–पोर्टल पर प्रकाशित किया जाए। निविदा प्रक्रिया से वित्तीय प्रस्ताव/कोटेशन निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त किए जाएंगे तथा तकनीकी रूप से अंर्ह पायी गई निविदाओं के वित्तीय प्रस्ताव/कोटेशन होने पर ही समिति के समक्ष उनके प्रस्ताव खोले जाएंगे।

(ग). जिस भी संस्था का वित्तीय प्रस्ताव न्यूनतम होगा उसी संस्था को कार्याबंटित किया जाएगा।

(घ). उक्त हेतु निगम स्तर पर अधिक सुस्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करते हुए नियमों को विस्तृत प्रक्रिया निगम स्तर पर तैयार करनी होगी जिसमे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस भी सूचीबद्ध संस्था को कार्य आबंटित हो उसकी प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी हो तथा संस्था का चयन न्यूनतम बिड मूल्य के आधार पर हो।

updesco

सन्दर्भ सं. : 3733
दिनाक : 14-1-2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,
उ.प्र. शासन।

विषयः <u>सॉफ्टवेयर विकास एवं स्टार्ट-अप हेतु संस्थाओं को सूचीबद्ध किये जाने विषयक गाइड लाइन्स के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के पत्र संख्या-1274/78-2-2020-135 आईटी/2016 दिनांक 27.11.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के नियंत्रणाधीन निगमों के प्रबन्ध निदेशकों की समिति में यथावश्यक संशोधनों पर संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

इस सम्बन्ध में संयुक्त सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के पत्र संख्या-1600(1)/78-2-2020-135आईटी/2016 दिनांक 30.12.2020 के क्रम में दिनांक 31.12.2020 को हुई बैठक में हुए विचार-विमर्श के अनुसार निगमों के एक-एक प्रतिनिधि की उपसमिति की संस्तुति के आधार पर प्रस्तावित संशोधनों का प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्नक पर दृष्टव्य है।

शासन कृपया अवलोकन कर शासन का अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

(नेहा प्रकाश)
प्रबन्ध निदेशक
यूपीडेस्को एवं श्रीट्रान

11/01/2021
(ऋषिरेन्द्र कुमार)
प्रबन्ध निदेशक
यूपीएलसी एवं अपट्रान पावरट्रानिक्स

उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लि.
(उ. प्र. सरकार का उपक्रम)

साफ्टवेयर विकास एवं स्टार्टअप हेतु संस्थाओं को सूचीबद्ध किये जाने विषयक गाइडलाइन्स के सम्बन्ध में दिनाँक 01.01.2021 को अपरान्ह 4:30 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्तः

उपस्थितिः

1. श्री राहुल पुरवार, वरिष्ठ प्रबन्धक, यूपीएलसी
2. श्री नूरूल होदा, प्रबन्धक (प्रणाली), यूपीडेस्को
3. श्री ए.पी. पवार, मैनेजर, श्रीट्रान इण्डिया लि.
4. श्री प्रबोध सिंह, प्रभारी, कारपोरेट, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि.

साफ्टवेयर विकास एवं स्टार्टअप हेतु संस्थाओं को सूचीबद्ध किये जाने विषयक गाइडलाइन्स के सम्बन्ध में आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 के पत्र संख्या 1600(1)/78–2–2020–135आईटी/2016 दिनाँक 30–12–2020 के माध्यम से शासनादेश संख्या 127/78–2–2019–135आईटी/2016 दिनाँक 11–03–2019 द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स में वाँछित संशोधन हेतु आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के नियंत्रणाधीन निगमों के प्रबन्ध निदेशकों की समिति में प्रस्तुत कर समिति की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

2– उक्त के अनुक्रम में यूपीडेस्को, यूपीएलसी, श्रीट्रान इण्डिया एवं अपट्रान पावरट्रानिक्स से एक–एक प्रतिनिधि नामित करते हुए 04 सदस्यों की एक उपसमिति गठित की गई। उपसमिति की बैठक में प्रकरण पर विचार–विमर्श किया गया। सर्विस प्रोवाइडर्स के इम्पैनलमेन्ट हेतु न्यूनतम अर्हता एवं मार्किंग सिस्टम में कतिपय संशोधन किये जाने की आवश्यकता है ताकि ओपेन मार्केट की अधिक से अधिक ऐसी फर्मों/संस्थाओं को इम्पैनलमेन्ट का अवसर प्राप्त हो सके। इससे आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अधीन निगमों को अद्यतन तकनीक की फर्मों/संस्थाओं को जोड़ा जा सकेगा। उपरोन्त के क्रम में निम्नवत सीमा तक संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं:–

3– **For Service Provider:**

Sr.	Existing Clause	Proposed Clause	Max. Marks
1	Company should be duly registered under Companies Act 1956/2013 or Society Registration Act 1860 having relevant registration.	Same as it is	---
2	Company should have executed projects for Central Govt/State Govt/PSU/ other Government Institution	Company should have executed projects for Central Govt/State Govt/PSU/ other Government Institution/Private Company registered in RoC/Society Registration Act 1860	---
3	Essential Requirment for Service Provider - Category "A": Should be at least one year old. Annual Turnover should be minimum Rs. 50 Lakhs. Category "B": Should be at least three years old. Average Annual Turnover of last three financial years should be minimum Rs.5 Cr. Category "C": Should be at least Four years old. Average Annual Turnover of last four years should be minimum Rs.10 Cr.	Essential Requirment for Service Provider - Category "A": Should be at least one year old. Annual Turnover should be minimum Rs 10 lakhs and upto Rs. 50 Lakhs. Category "B": Should be at least three years old. Average Annual Turnover of last three financial years should be above Rs 50 Lakhs to Rs. 5 Cr. Category "C": Should be at least Four years old. Average Annual Turnover of last four years should be above Rs 5 Cr.	---

4	**For Service Provider Category "A":** Company Turnover for last Financial year should be minimum Rs. 50 Lakhs Rs 50 Lacs <=70 Lacs ~ 5 Marks >Rs 70 Lacs <=90 Lacs ~ 10 Marks >Rs 90 Lacs <=110 Lacs ~ 15 Marks >Rs 110 Lacs ~ 20 Marks	**For Service Provider Category "A":** Company Turnover for last Financial year should be upto Rs. 50 Lakhs Rs 10 Lacs <=20 Lacs ~ 5 Marks >Rs 20 Lacs <=30 Lacs ~ 10 Marks >Rs 30 Lacs <=40 Lacs ~ 15 Marks >Rs 40 Lacs <=50 Lacs ~ 20 Marks	Turnover
5	**For Service Provider Category "B":** Company average annual turnover for last 3 Financial years should be minimum Rs. 5 Cr. Rs 5 Cr <= 7 Cr ~ 5 Marks >Rs 7 Cr <= 10 Cr ~ 10 Marks >Rs 10 Cr <= 15 Cr ~ 15 Marks >Rs 15 Cr ~ 20 Marks	**For Service Provider Category "B":** Company average annual turnover for last 3 Financial years should be above Rs 50 Lakhs to Rs. 5 Cr. Rs 50 Lac <= 2 Cr ~ 5 Marks >Rs 2 Cr <= 3 Cr ~ 10 Marks >Rs 3 Cr <= 5 Cr ~ 15 Marks >Rs 5 Cr ~ 20 Marks	20
6	**For Service Provider Category "C":** Company average annual turnover for last 4 Financial years should be minimum Rs.10 Cr Rs 10 Cr <= 15 Cr ~ 5 Marks >Rs 15 Cr <= 20 Cr ~ 10 Marks >Rs 20 Cr <= 25 Cr ~ 15 Marks >Rs 25 Cr ~ 20 Marks	**For Service Provider Category "C":** Company average annual turnover for last 4 Financial years should be above Rs. 5 Cr. Rs 5 Cr <= 10 Cr ~ 5 Marks >Rs 10 Cr <= 15 Cr ~ 10 Marks >Rs 15 Cr <= 20 Cr ~ 15 Marks >Rs 20 Cr ~ 20 Marks	
7	**For Service Provider Category "A":** Company should have executed projects for Central Govt./State Govt. / PSU/ other Govt. Institution having minimum value of Rs. 5 Lacs or above 2 Projects → 15 Marks 3 Projects → 20 Marks 4 Projects → 25 Marks 5 Projects or above →30 Marks	**For Service Provider Category "A":** Company should have executed projects for Central Govt./State Govt. / PSU/ other Govt. Institution/Private Companies registered in RoC/Society Registration Act 1860 having minimum value of Rs. 5 Lacs or above 2 Projects → 15 Marks 3 Projects → 20 Marks 4 Projects → 25 Marks 5 Projects or above →30 Marks	
8	**For Service Provider Category "B":** Company should have executed projects for Central Govt/State Govt. / PSU/ other Govt. Institution having minimum value of Rs. 10 Lacs or above 3 Projects → 20 Marks 4 Projects → 25 Marks 5 Projects or above →30 Marks	**For Service Provider Category "B":** Company should have executed projects for Central Govt./State Govt. / PSU/ other Govt. Institution/Private Companies registered in RoC/Society Registration Act 1860 having minimum value of Rs. 10 Lacs or above 3 Projects → 20 Marks 4 Projects → 25 Marks 5 Projects or above →30 Marks	work order 30
9	**For Service Provider Category "C":** Company should have executed projects for Central Govt./State Govt. / PSU/ other Govt. Institution having minimum value of Rs. 50 Lacs or above 3 Projects → 20 Marks 4 Projects → 25 Marks 5 Projects or above →30 Marks	**For Service Provider Category "C":** Company should have executed projects for Central Govt./State Govt. / PSU/ other Govt. Institution/Private Companies registered in RoC/Society Registration Act 1860 having minimum value of Rs. 50 Lacs or above 3 Projects → 20 Marks 4 Projects → 25 Marks 5 Projects or above →30 Marks	

10	**For Service Provider Category "A":** Company should submit at least one running work order of minimum value of Rs 5 lacs of any Central Govt/State Govt/PSU/ other Government Institution. ~ 15 marks	**For Service Provider Category "A":** Company should have executed projects for Central Govt./State Govt./PSU/ other Govt. Institution having minimum value of Rs. 5 Lacs or above 1 Projects → 5 Marks 2 Projects → 10 Marks 3 Projects → 15 Marks	
11	**For Service Provider Category "B":** Company should submit at least one running work order of minimum value of Rs 10 lacs of any Central Govt/State Govt/PSU/ other Government Institution. ~ 15 marks	**For Service Provider Category "B":** Company should have executed projects for Central Govt./State Govt./PSU/ other Govt. Institution having minimum value of Rs. 10 Lacs or above 1 Projects → 5 Marks 2 Projects → 10 Marks 3 Projects → 15 Marks	Current Projects 15
12	**For Service Provider Category "C":** Company should submit at least one running work order of minimum value of Rs 50 lacs of any Central Govt/State Govt/PSU/ other Government Institution. ~ 15 marks	**For Service Provider Category "C":** Company should have executed projects for Central Govt./State Govt./PSU/ other Govt. Institution having minimum value of Rs. 50 Lacs or above 1 Projects → 5 Marks 2 Projects → 10 Marks 3 Projects → 15 Marks	
13	Company should have ISO or CMMI Certification ISO 9001:2008 or CMMI Level 3 → 10 Marks, ISO 27001:2013 or CMMI Level 5 → 15 Marks	Same as it is	15
14	**For Service Provider Category "A":** Company should have 5 manpower on Roll for project handling out of which at least 3 Technical staff must have (MCA/B.Tech/BE/ M.Tech/ M.Sc.IT) < 05 -- 0 Mark 05 to 10 -- 5 Marks 11 to 15 -- 10 Marks 16 to 20 -- 15 Marks Above 20 -- 20 Marks	Same as it is	
15	**For Service Provider Category "B":** Company should have 15 manpower on Roll for project handling out of which at least 10 Technical staff must have (MCA/B.Tech/BE/ M.Tech/ M.Sc.IT) < 15 -- 0 Mark 15 to 25 -- 5 Marks 26 to 35 -- 10 Marks 36 to 45 -- 15 Marks Above to 45 -- 20 Marks	Same as it is	20
16	**For Service Provider Category "C":** Company should have 30 manpower on Roll for project handling out of which at least 25 Technical staff must have (MCA/B.Tech/BE/ M.Tech/ M.Sc.IT) < 30 -- 0 Mark 30 to 40 -- 5 Marks 41 to 50 -- 10 Marks 51 to 60 -- 15 Marks Above 60 -- 20 Marks	Same as it is	
17	Minimum Qualifying Marks are 60 out of 100	Same as it is	100

उपरोक्तानुसार तकनीकी मूल्याँकन में किसी भी प्रोजेक्ट पर उक्त क्र.सं. 7, 8 एवं 9 अथवा 10, 11 एवं 12 में से किसी एक स्थान पर ही अंक दिए जा सकेंगे।

कैटेगरीवार सर्विस प्रोवाइडर की किसी भी प्रोजेक्ट पर कार्य सम्पादन की क्षमता निम्नानुसार रखी जानी प्रस्तावित है:–

1 Service Providers competent to provide services for a single project with an estimated value up to Rs 25 lakhs -- **Category –'A'.**
2 Service providers competent to provide services for a single project with an estimated value upto Rs. 75 lakhs -- **Category –'B'.**
3 Service providers competent to provide services for a single project with an estimated value upto Rs 500 lakhs -- **Category –'C'.**

उपरोक्तानुसार शासकीय विभागों/संस्थाओं से प्राप्त कार्यादेश जिसकी अनुमानित धनराशि रु 5.00 करोड़ (निगम के संस्थागत शुल्क रहित) से अधिक होगी, ऐसे कार्यों में खुली ई–निविदा को वरीयता दी जायेगी। new Addition

शेष नियम व शर्तें शासनादेश संख्या 127/78–2–2019–135आईटी/2016 दिनाँक 11–03–2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार यथावत रखे जाने पर संस्तुति की गई। अन्त में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(राहुल पुरवार)	(नूरूल होदा)	(ए.पी. पवार)	(प्रबोध सिंह)
वरिष्ठ प्रबन्धक	प्रबन्धक (प्रणाली)	मैनेजर	प्रभारी, कारपोरेट
यूपीएलसी	यूपीडेस्को	श्रीट्रान इण्डिया लि.	अपट्रान पावरट्रानिक्स लि.

updesco

3372
16.12.2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,
उ0प्र0 शासन।

विषय : सॉफ्टवेयर विकास एवं स्टार्ट-अप हेतु संस्थाओं को सूचीबद्ध किये जाने विषयक गाइड लाइन्स के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के पत्र संख्या 1274/78-2-2020-135आईटी/2016 दिनांक 27.11.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के नियत्रणाधीन निगमों के प्रबन्ध निदेशकों की समिति में यथावश्यक संशोधनों पर संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

निर्देशानुसार निगमों द्वारा विचार-विमर्श करके सॉफ्टवेयर विकास एवं स्टार्ट-अप हेतु संस्थाओं को सूचीबद्ध किये जाने विषयक समस्त निगमों के एक-एक प्रतिनिधि की उपसमिति की संस्तुति के आधार पर प्रस्तावित संशोधनों का प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्नक पर दृष्टव्य है।

शासन कृपया अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

15/12/2020

(नेहा प्रकाश)
प्रबन्ध निदेशक
यूपीडेस्को एवं श्रीट्रान

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
प्रबन्ध निदेशक
यूपीएलसी एवं अपट्रान पावरट्रानिक्स

साफ्टवेयर विकास एवं स्टार्टअप हेतु संस्थाओं को सूचीबद्ध किये जाने विषयक गाइडलाइन्स के सम्बन्ध में दिनाँक 07.12.2020 को अपरान्ह 4:30 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्तः

उपस्थितिः

1. श्री राहुल पुरवार, वरिष्ठ प्रबन्धक, यूपीएलसी
2. श्री नूरूल होदा, प्रबन्धक (प्रणाली), यूपीडेस्को
3. श्री ए.पी. पवार, मैनेजर, श्रीट्रान इण्डिया लि.
4. श्री प्रबोध सिंह, प्रभारी, कारपोरेट, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि.

साफ्टवेयर विकास एवं स्टार्टअप हेतु संस्थाओं को सूचीबद्ध किये जाने विषयक गाइडलाइन्स के सम्बन्ध में आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 के पत्र संख्या 1274/78–2–2020–135आईटी/2016 दिनाँक 27–11–2020 के माध्यम से शासनादेश संख्या 127/78–2–2019–135आईटी/2016 दिनाँक 11–03–2019 द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स में वाँछित संशोधन हेतु आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के नियंत्रणाधीन निगमों के प्रबन्ध निदेशकों की समिति में प्रस्तुत कर समिति की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के अनुक्रम में यूपीडेस्को, यूपीएलसी, श्रीट्रान इण्डिया एवं अपट्रान पावरट्रानिक्स से एक–एक प्रतिनिधि नामित करते हुए 04 सदस्यों की एक उपसमिति गठित की गई। उपसमिति की बैठक में प्रकरण पर विचार–विमर्श किया गया। सर्विस प्रोवाइडर्स के इम्पैनलमेन्ट हेतु न्यूनतम अर्हता एवं मार्किंग सिस्टम में कतिपय संशोधन किये जाने की आवश्यकता है ताकि ओपेन मार्केट की अधिक से अधिक ऐसी फर्मों/संस्थाओं को इम्पैनलमेन्ट का अवसर प्राप्त हो सके। इससे आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अधीन निगमों को अद्यतन तकनीक की फर्मों/संस्थाओं को जोड़ा जा सकेगा। उपरोन्त के क्रम में निम्नवत सीमा तक संशोधन प्रस्तावित किये गये हैः–

2. **For Service Provider:**

Sr.	Existing Clause	Proposed Clause
1	Company should be duly registered under Companies Act 1956/2013 or Society Registration Act 1860 having relevant registration.	Same as it is
2	Central Govt/State Govt/PSU/ other Government Institution	Same as it is
3	Essential Requirment for Service Provider - **Category "A":** Should be at least one year old. Annual Turnover should be minimum Rs. 50 Lakhs. **Category "B":** Should be at least three years old. Average Annual Turnover of last three financial years should be minimum Rs.5 Cr. **Category "C":** Should be at least Four years old. Average Annual Turnover of last four years should be minimum Rs.10 Cr.	Essential Requirment for Service Provider - **Category "A":** Should be at least one year old. Annual Turnover should be upto Rs. 50 Lakhs. **Category "B":** Should be at least three years old. Average Annual Turnover of last three financial years should be above Rs 50 Lakhs to Rs. 5 Cr. **Category "C":** Should be at least Four years old. Average Annual Turnover of last four years should be above Rs 5 Cr.

राहुल 07.12.2020 नूरूलहोदा 7/12/2020 7.12.20

4	**For Service Provider Category "A":** Company Turnover for last Financial year should be minimum Rs. 50 Lakhs Rs 50 Lacs <=70 Lacs ~ 5 Marks >Rs 70 Lacs <=90 Lacs ~ 10 Marks >Rs 90 Lacs <=110 Lacs ~ 15 Marks >Rs 110 Lacs ~ 20 Marks	**For Service Provider Category "A":** Company Turnover for last Financial year should be upto Rs. 50 Lakhs Rs 20 Lacs <=30 Lacs ~ 5 Marks >Rs 30 Lacs <=40 Lacs ~ 10 Marks >Rs 40 Lacs <=50 Lacs ~ 15 Marks >Rs 50 Lacs ~ 20 Marks
5	**For Service Provider Category "B":** Company average annual turnover for last 3 Financial years should be minimum Rs. 5 Cr. Rs 5 Cr <= 7 Cr ~ 5 Marks >Rs 7 Cr <= 10 Cr ~ 10 Marks >Rs 10 Cr <= 15 Cr ~ 15 Marks >Rs 15 Cr ~ 20 Marks	**For Service Provider Category "B":** Company average annual turnover for last 3 Financial years should be above Rs 50 Lakhs to Rs. 5 Cr. Rs 50 Lac <= 2 Cr ~ 5 Marks >Rs 2 Cr <= 3 Cr ~ 10 Marks >Rs 3 Cr <= 5 Cr ~ 15 Marks >Rs 5 Cr ~ 20 Marks
6	**For Service Provider Category "C":** Company average annual turnover for last 4 Financial years should be minimum Rs.10 Cr Rs 10 Cr <= 15 Cr ~ 5 Marks >Rs 15 Cr <= 20 Cr ~ 10 Marks >Rs 20 Cr <= 25 Cr ~ 15 Marks >Rs 25 Cr ~ 20 Marks	**For Service Provider Category "C":** Company average annual turnover for last 4 Financial years should be above Rs. 5 Cr. Rs 5 Cr <= 10 Cr ~ 5 Marks >Rs 10 Cr <= 15 Cr ~ 10 Marks >Rs 15 Cr <= 20 Cr ~ 15 Marks >Rs 20 Cr ~ 20 Marks
7	**For Service Provider Category "A":** Company should have executed projects for Central Govt./State Govt. / PSU/ other Govt. Institution having minimum value of Rs. 5 Lacs or above 2 Projects → 15 Marks 3 Projects → 20 Marks 4 Projects → 25 Marks 5 Projects or above →30 Marks	**For Service Provider Category "A":** Company should have executed projects for Central Govt./State Govt. / PSU/ other Govt. Institution having minimum value of Rs. 5 Lacs or above 2 Projects → 10 Marks 3 Projects → 15 Marks 4 Projects or above → 20 Marks Company should have executed projects for Private Companies registered in RoC/Society Registration Act 1860 having minimum value of Rs. 5 Lacs or above 2 Projects → 5 Marks 3 Projects or above → 10 Marks
8	**For Service Provider Category "B":** Company should have executed projects for Central Govt/State Govt. / PSU/ other Govt. Institution having minimum value of Rs. 10 Lacs or above 3 Projects → 20 Marks 4 Projects → 25 Marks 5 Projects or above →30 Marks	**For Service Provider Category "C":** Company should have executed projects for Central Govt./State Govt. / PSU/ other Govt. Institution having minimum value of Rs. 10 Lacs or above 3 Projects → 10 Marks 4 Projects → 15 Marks 5 Projects or above → 20 Marks Company should have executed projects for Private Companies registered in RoC/Society Registration Act 1860 having minimum value of Rs. 10 Lacs or above 3 Projects → 5 Marks 4 Projects or above → 10 Marks

9	**For Service Provider Category "C":** Company should have executed projects for Central Govt./State Govt. / PSU/ other Govt. Institution having minimum value of Rs. 50 Lacs or above 3 Projects → 20 Marks 4 Projects → 25 Marks 5 Projects or above →30 Marks	**For Service Provider Category "C":** Company should have executed projects for Central Govt./State Govt. / PSU/ other Govt. Institution having minimum value of Rs. 50 Lacs or above 3 Projects → 10 Marks 4 Projects → 15 Marks 5 Projects or above → 20 Marks Company should have executed projects for Private Companies registered in RoC/Society Registration Act 1860 having minimum value of Rs. 50 Lacs or above 3 Projects → 5 Marks 4 Projects or above → 10 Marks
10	**For Service Provider Category "A":** Company should submit at least one running work order of minimum value of Rs 5 lacs of any Central Govt/State Govt/PSU/ other Government Institution. ~ 15 marks	**For Service Provider Category "A":** Company should submit at least one running work order of minimum value of Rs 5 lacs of any Central Govt/State Govt/PSU/ other Government Institution. ~ 10 marks Company should submit at least one running work order of minimum value of Rs 5 lacs of any Private Company registered in RoC/Society Registration Act 1860 ~ 5 marks
11	**For Service Provider Category "B":** Company should submit at least one running work order of minimum value of Rs 10 lacs of any Central Govt/State Govt/PSU/ other Government Institution. ~ 15 marks	**For Service Provider Category "B":** Company should submit at least one running work order of minimum value of Rs 10 lacs of any Central Govt/State Govt/PSU/ other Government Institution. ~ 10 marks Company should submit at least one running work order of minimum value of Rs 10 lacs of any Private Company registered in RoC/Society Registration Act 1860 ~ 5 marks
12	**For Service Provider Category "C":** Company should submit at least one running work order of minimum value of Rs 50 lacs of any Central Govt/State Govt/PSU/ other Government Institution. ~ 15 marks	**For Service Provider Category "C":** Company should submit at least one running work order of minimum value of Rs 50 lacs of any Central Govt/State Govt/PSU/ other Government Institution. ~ 10 marks Company should submit at least one running work order of minimum value of Rs 50 lacs of any Private Company registered in RoC/Society Registration Act 1860 ~ 5 marks
13	Minimum Qualifying Marks are 60 out of 100	Same as it is

शेष नियम व शर्तें शासनादेश संख्या 127/78–2–2019–135आईटी/2016 दिनाँक 11–03–2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार यथावत रखे जाने पर संस्तुति की गई। अन्त में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(राहुल पुरवार) 07.12.2020	(नूरूल होदा)	(ए.पी. पवार) 7/12/2020	(प्रबोध सिंह) 7.12.20
वरिष्ठ प्रबन्धक	प्रबन्धक (प्रणाली)	मैनेजर	प्रभारी, कारपोरेट
यूपीएलसी	यूपीडेस्को	श्रीट्रान इण्डिया लि.	अपट्रान पावरट्रानिक्स लि

UPLC-H.Q.
Reg No.: 3048
Date: 25/1/2021

<u>बैठक दिनांक 25-01-2021 पूर्वान्ह 11:30 बजे</u>

<u>संख्या-189 /78-2-2021-135आईटी/2016</u>

प्रेषक,

बराती लाल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, अशोकमार्ग लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, गोमतीनगर लखनऊ।

<u>आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2</u>   <u>लखनऊ:दिनांक: 22जनवरी, 2021</u>

विषय:- साफ्टवेयर विकास एवं स्टार्ट-अप हेतु संस्थाओं को सूचीबद्ध किये जाने विषयक पूर्व में निर्गत गाइड लाइन्स में कतिपय संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित यूपीडेस्को, लखनऊ के पत्र संख्या-3733 दिनांक 14-01-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि साफ्टवेयर विकास एवं स्टार्ट-अप हेतु संस्थाओं को सूचीबद्ध किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-127/78-2-2019-135आईटी /2016 दिनांक 11-3-2019 द्वारा निर्धारित गाइड लाइन्स में संशोधन किये जाने हेतु जो प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराया गया है उसके परीक्षण में इम्पैनल्ड वेन्डर से प्रोक्योरमेन्ट करने की प्रक्रिया में कई बिन्दु सामने आये है जैसे वेन्डर को निविदा की सूचना की प्रक्रिया, प्रोसेसिंग डिपार्टमेन्ट से आदान प्रदान की कमी, सक्षम स्तर से अनुमति लिये बिना पत्राचार करना आदि के साथ- साथ आरएफपी में भी कई संशोधन किया जाना आवश्यक पाया गया है।

3- उपरोक्त प्रकरण पर विचार विमर्श किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में **दिनांक 25-01-2021 को पूर्वान्ह 11:30 बजे सी-ब्लाक, लोक भवन प्रथम तल स्थित सभा कक्ष संख्या-109 में आहूत की गयी है।**

4- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त बैठक में निर्धारित तिथि व समय पर सुसंगत सूचनाओं सहित भिज्ञ अधिकारियों के साथ **स्वयं** प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इले0 विभाग, उ0प्र0शासन।
2- विशेष सचिव, (आर/ एन) आईटी एवं इले0 विभाग, उ0प्र0शासन।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव